Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 5 | ISSUE : 9 | SEPTEMBER 2019

वैशाली जिला में ग्रामीण विकास की स्थिति: एक भौगोलिक अध्ययन

राकेश भारती [1] | डॉ. शम्भूशरण प्रसाद [2]

[1] शोध–छात्र (भूगोल) मगध विश्वविद्यालय, बोध–गया.

[2] सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर आर०के०डी० कॉलेज, पटना.

ABSTRACT:

वैशाली जिला भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश गंगा के मैदान का एक छोटा सा अंश है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा वाहित मलवें के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। वैशाली जिला 25° 30′ उत्तरी अक्षांश से 26°2′ उत्तरी अक्षांश तक तथा 85°15′ पूर्वी देशांतर से 85°30′ पूर्वी देशांतर के स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2036 वर्ग कि०मी० है। यहाँ की कुल आबादी 34,95,021 हैं, जिसमें ग्रामीण आबादी 32,61,942 हैं। अर्थात कुल जनसंख्या का 93.33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वैशाली जिला में है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े कार्यक्रमों, जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, आवास, कुटीर, उद्योग, सामाजिक कल्याण एवं सरकारी योजनाओं आदि के द्वारा जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हैं–यहाँ आम, लीची, केला के बागान भी बहुतायत रूप में पाये जाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि पद्धति, नये तकनीक, वैज्ञानिक उपकरण, उन्नत बीज और सुदृढ़ बाजार व्यवस्था की आवश्यकता हैं अन्यथा यह क्षेत्र विकास के दौड़ में पीछे छूट जायेगा। बिहार सरकार ग्रामीण विकास की नीतियों पर अमल करे, कृषि रोड़ मैप और बिजली की सामुचित व्यवस्था कर दे तो यहाँ बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी विकसित किये जा सकते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोतम उपयोग करना हैं।

KEYWORDS:

ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई, आवास, सामाजिक कल्याण, सरकारी योजनायें।

परिचय :

भारत गाँवों का देश हैं। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं, जिनके जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि हैं और राष्ट्रीय आय का प्रधान स्रोत हैं। गाँधी जी ने गाँवों के महत्व को दर्शातों हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ″हमारे यहाँ गाँवों के उन्नयन या विकास के बिना भारत के विकास की बात सोचना मूर्खता हैं, क्योंकि गाँवों में ही भारत निहित हैं।″ वर्तमान भारत के आबादी की मात्र 30% (लगभग) नगरीय जनसंख्या की उन्नति से ही भारत विकसित नहीं हो सकता हैं। देश की आर्थिक विकास की धुरी हमारे गाँव ही हैं। विकास के संदर्भ में आजादी के बाद देश में पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ, तब से गाँवों के विकास के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठये गये हैं। साथ ही अनेक योजनाओं भी बनती रही हैं। जैसे–राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन अधिनियम, काम के बदले अन्य कार्यक्रम इंदिरा/प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा इत्यादि। इसी तरह पंचायती राज योजना ने भी गाँवों के विकास में नई जान फूकी, किंतु बिहार को जितना विकास होना चाहिये उतना नहीं हो पाया हम अपने देश के अन्य कई राज्यों के मुकाबले आज भी बहुत पीछे हैं। बंटवारे के बाद वर्तमान बिहार के विकास के लिए कृषि का विकास और उस पर आधारित उद्योगों के विकास से ही ग्रामीण विकास को गति दिया जा सकता हैं। यहाँ से ही ग्रामीण विकास को गति दिया जा सकता हैं। यहाँ की 70% जनसंख्या स्वयं कृषक हैं, कृषक मजदूर हैं, या कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। जो गाँवों में निवास करते है। अतः ग्रामीण विकास को मूर्त रूप देने के लिए हमें कृषि को अत्यधिक विकसित करने की आवश्यकता हैं। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊँ है अतः कृषि विकास की अत्यधिक सम्भावनाएँ हैं। यहाँ भूमि सुधार किया गया और हरित क्रांति का भी प्रयोग हुआ किंतु प्रत्याशित सफलता नहीं मिली। अतः वैज्ञानिक ढंग से भूमि उपयोग करने एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता हैं।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होती है कि ग्रामीण विकास एक बहुआयामी घटक हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना बद्ध प्रयास करने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े कार्यक्रमों जैसे–कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, आवास, कुटीर उद्योग, सामाजिक कल्याण एवं सरकारी योजनाओं आदि के द्वारा जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी व्यूह रचना है जिसका उद्देश्य विकास के लाभो को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के तलाश में लगे निर्धनतम् लोगों तक पहुँचाना हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवता में सुधार के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना हैं।

बिहार का वैशाली जिला भी मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश लिये हुए है। यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश गंगा के मैदान का एक छोटा सा अंश है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लायी गयी जलोढमिट्टी से बना हैं। यह भू–भाग अत्यधिक उपजाऊँ हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किये जाते हैं। धान गेहूँ, दलहन, तिलहन और सब्जियों की खेती प्रचूर मात्रा में होते है, साथ ही बड़े पैमाने पर केला, आम, लीची के बगान भी बहुतायत रूप से पाये जाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि पद्धति, नये तकनिक, वैज्ञानिक उपकरण, उन्नत बीज और सुदृढ़ बाजार की आवश्यकता हैं अन्यथा यह क्षेत्र विकास के दौड़ में पीछे छूट जायेगा। बिहार सरकार ग्रामीण विकास की नीतियों पर अमल करे, कृषि रोड़ मैप और बिजली की समुचित व्यवस्था कर दे तो यहाँ बड़ें पैमाने

पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी विकसित किये जा सकते हैं।

ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि–"ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की रणनीति हैं।"

ग्रामीण विकास की रणनीति में 'राज्य एवं केन्द्र की भूमिका अहम होती हैं। राज्य, केंद्र एवं सामूहिक प्रयास से गाँवों के विकास के कार्य होते रहे हैं। ग्रामीण विकास केवल कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास से ही संभव नहीं है। इसके लिए ग्रामीण परिपेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियाएँ ग्रामीण विकास की परिधि में सम्मिलित हैं।

उद्देश्य :

वर्तमान शोध–पत्र वैशाली जिला के ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं। इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है :

1. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में आधारभूत संरचनाओं का योगदान।
2. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों एवं घरेलू उद्योगों का योगदान।
3. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में कृषि के योगदान का अध्ययन।
4. वैशाली जिला बैंकों की स्थिति एवं ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका का अध्ययन।
5. वैशाली जिला के गाँवों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
6. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का योगदान।

HYPOTHESIS (परिसंकल्पना) :

वर्तमान शोध–पत्र निम्नांकित परिसंकल्पनाओं पर आधारित हैं :

1. वैशाली जिला में ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध भौतिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता हैं।
2. वैशाली जिला के कृषि विकास के उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज, रसायनिक उर्वरक, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं सिंचाई के साधनों का प्रभाव पड़ता हैं।
3. ग्रामीण विकास को वैशाली जिला का बाजार और नगरीय क्षेत्र भी प्रभावित करता है।
4. वैशाली जिला के ग्रामीण विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का प्रभाव पड़ता हैं।
5. वैशाली जिला में ग्रामीण विकास के अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन में सरकार का काफी योगदान हैं।

विधितंत्र :

प्रस्तुत शोध–पत्र में अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधितत्रों का व्यवहार करते हुए विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़े का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के आँकड़े अध्ययन क्षेत्र में भ्रमण कर ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव इत्यादि के अलावे ग्रामीण लोगों से मिलकर प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त किया गया हैं। इसके अलावे द्वितीयक आँकडे की प्राप्ति डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मुजफ्फरपुर, Hand book of vaishali, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, जिला उधोग कार्यालय, इत्यादि से आँकड़े एकत्र किये हैं। साथ ही प्रखण्ड़ और पंचायत से भी आँकड़े एकत्र किये है। इसके अलावा अन्य पुस्तकें, मैग्जीन एवं पत्र–पत्रिकाओं में प्राप्त किया गया हैं। तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार इसे शोध–पत्र में सम्मिलित किया गया हैं।

अध्ययन क्षेत्र :

अध्ययन क्षेत्र वैशाली जिला मध्य गंगा के उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित हैं। इस जिला का निर्माण 1972 ई॰ में मुजफ्फरपुर जिला से अलग होकर बना है। इसका मुख्यालय हाजीपुर हैं। वैशाली जिला का अक्षांशीय विस्तार 25°30′ उत्तरी अक्षांश से 26°02′ उत्तरी अक्षांश और 85°03 ′पूर्वी देशांतर में 85°38′पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2036 वर्ग कि.मी. हैं। वैशाली जिला के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में समस्तीपुर और पश्चिम में सारण जिला इसके सीमा का निर्धारण करते है। 2011 ई॰ के जनगणना के अनुसार इस जिला की कुल आबादी 3495021 है। इसका घनत्व 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हैं। गंगा नदी पर महात्मा गाँधी सेतु के निर्माण के बाद दक्षिणी बिहार से प्रत्यक्ष सम्पर्क में जुड़ गया है। साथ ही वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर पटना का सेटेलाईट सिटी हैं। ग्रेटर पटना में हाजीपुर को भी शामिल किया गया है। इसका विकास तीव्र गति से होने लगा हैं। इस जिला के कुल ग्रामीण जनसंख्या 3261942 (2011) हैं। अर्थात जिला के कुल जनसंख्या का 93.33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हैं।

वैशाली जिला में ग्रामीण विकास की स्थिति :

भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है और बिना आत्मा के विकसित किये सर्वागीण विकास असंभव है।

निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वैशाली जिला को विकसित किया जा रहा है। जैसे–

1. **मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना।**

   (a) **आर्थिक हल युवाओं को बल :** इसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2018–19 में 901 छात्र एवं छात्रों को स्वीकृत किया गया हैं

   मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2018–19 के 10967 छात्र एवं छात्राओं को स्वीकृत किया गया हैं।

   कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत 2018–19 में 20269 आवेदकों को स्वीकृत किया गया है।

   (b) आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार : इसके तहत वैशाली जिला में 2018–19 में 513 कर्मियों की नियुक्ति किया गया, जिसमें 217 स्थायी एवं 296 संविदा पर नियुक्त किये गये हैं।

   (c) हर घर बिजली लगातार : इसके तहत 89048 घरों को बिजली देने हेतु लक्षित किया गया है। 31/03/16 तक 330645 घरों तक बिजली उपलब्ध करा दिया गया हैं।

   (d) हर घर नल का जल इसके तहत 2018–19 में 1025 वार्डों में हर घर नल का जल लगाया जा चुका हैं।

   (e) घर तक पक्की गली नालियाँ : इसके तहत 2018–19 में 1913 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका हैं।

   (f) शौचालय निर्माण, घर का सम्मान : इसके तहत 359453 घरों में 2018–19 में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया हैं।

   (g) अवसर बढ़े, आगे बढ़े : इसके तहत जिला में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा मेड़िकल संस्थान इत्यादि की स्थापना किया जा रहा है।

2. **मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) :**

E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 5 | ISSUE : 9 | SEPTEMBER 2019

इसका शुरूआत 2006 ई॰ में हुआ था, इसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले इच्छुक व्यस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना हैं। इसके तहत वैशाली जिला में 2018–19 में 97962 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया हैं। इसके तहत गौ शेड़, तालाब का निर्माण चबुतरा का निर्माण इत्यादि योजनाएँ चलाये जा रहे हैं।

3. **इंदिरा/प्रधानमंत्री आवास योजना :** इसके तहत बेघर या अपर्याप्त आवासीय सुविधाओं वाले बी.पी.एल परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती हैं। इसके तहत 2018–19 में वैशाली जिला में 42878 बी.पी.एल परिवारों को राशि दी गयी है।

4. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :** इस योजना की शुरूआत 25 दिसंबर 2000 ई॰ को किया गया था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले और पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले सड़क–संपर्क से वंचित गाँवों को जोड़ना हैं। वैशाली जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा काफी गाँवों को जोड़ा गया हैं।

5. **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :** इसके तहत वैशाली जिला में सड़क का निर्माण हुआ है, और हो रहा हैं, इसके तहत '500 तक की आबादी वाले सभी टोले में पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत महादलित, दलित, और पिछड़ी जातियों के टोलों को प्राथमिकता दी जाती हैं।

6. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :** इस योजना का शुरूआत 2015 ई॰ में हुआ था। इस योजना के तहत 2020 ई॰ तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना हैं। इसके तहत सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार देना हैं। वैशाली जिला में इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा हैं।

इसके अलावा भी वैशाली जिला के ग्रामीण विकास हेतु अन्य योजना जैसे–जीविका, महिला सशक्तीकरण, SC/ST जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए प्रयास इत्यादि चलाया जा रहा हैं।

निष्कर्ष : इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैशाली जिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोगों का जीवन–स्तर में आपेक्षित सुधार हुआ हैं। लेकिन सुधारों के बावजूद भी अभी भी वहाँ सुधार करने की जरूरत हैं, क्योंकि अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़ी हुई हैं। एवं लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं रहने के कारण वहाँ के लोग सरकारी योजनाओं का सही से फायदा नहीं उठा पाते हैं।

REFERENCES

1. तिवारी, रामचंद्र 2016 : भारत का भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

2. श्रीवास्तव, बी.के., शर्मा, एन. चौहान, बी.आर. (2006), प्रादेशिका नियोजन एवं संतुलित विकास, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर,

3. सिंहा, डी.पी. (2019), बिहार की नयी योजनाएँ, विभागीय प्रकाशन बिक्री केंद्र, पटना–15

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2011 से 2015 तक।

5. आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार 2011 से 2019 तक।

6. योजना मासिक पत्रिका 2011 से 2019 तक।

7. अग्रवाल, अनुपम एवं अग्रवाल, शरद 2016; अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन आगरा।

8. Akela, Anil kumar, 2015: Possbilitties of food processing industery in Bihar: Geographical perspective, vol 16, pp. 111-119.

9. Pratap, Rana 2011: Rehabilitation of the economy of Bihar, Jharkhand through sastainable agriculture. Geographical prospective, vol 12, pp. 32-47.